

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वि0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून दिनांक: 13 फरवरी, 2009

विषय:- वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 132/वि0अनु0-3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था, शासनादेश संख्या: 444/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 13 जून, 2002 के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता एवं शासनादेश संख्या: 916/वि0अनु0-3/2003 दिनांक 5 जून, 2003 के द्वारा नैनीताल के शहरी क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में कमश: आयुक्त कुमायूँ मण्डल एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात् मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप इन नगरों को "बी-2" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

2-वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति-2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(ग्रु0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैंड के समतुल्य अनुमन्य बैंड-पे के आधार पर "बी 2" श्रेणी हेतु ग्रेड-पे का 75 प्रतिशत, "सी" श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों को 50 प्रतिशत तथा

समस्त "अवर्गीकृत क्षेत्रों" को 40 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	ग्रेड वेतन (रु०)	श्रेणी "बी-2" देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनजातीय मुख्यालय, हरिद्वार, (शहरी क्षेत्र) काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रुड़की (शहरी) अल्मोडा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल (शहरी क्षेत्र) गोपेश्वर (घमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग।	"अवर्गीकृत श्रेणी" उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	525	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1660
10.	4600	3450	2300	1840
11.	4800	3600	2200	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14.	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

3-ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्ण वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे-बैंड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4-अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

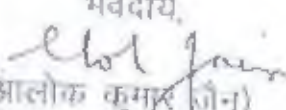
5-ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

6-संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं। अथवा अपनी निजी आवास में निवास करते हैं।

7-ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0 टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना बनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 132/वि0अनु0-3/2001 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2001 एवं संख्या: 444/वि0अनु0-3/2002 दिनांक: 13 जून, 2002 की उक्त दरों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

8-यह आदेश 1 अप्रैल, 2009 से लागू लागू होंगे।

9-अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

 (आलोक कुमार जैन)
 प्रमुख सचिव वित्त।